National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2025; 1(61): 87-90
© 2025 NJHSR
www.sanskritarticle.com

डॉ. कुमार बागेवाडिमठ
सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग,
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
तिरुपति (आ.प्र)

Correspondence:
डॉ. कुमार बागेवाडिमठ
सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग,
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
तिरुपति (आ.प्र)

समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए एक नया दृष्टिकोण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 और भारतीय उच्च शिक्षा का भविष्य

डॉ. कुमार बागेवाडिमठ

उपोद्घात

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) देश की कठोर, विशिष्ट और परीक्षा-केंद्रित उच्च शिक्षा की विरासत से एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था की तेज़ी से बदलती माँगों को समझते हुए, एनईपी -2020 लचीलेपन, समग्र शिक्षा और बहु-विषयक जुड़ाव पर आधारित एक परिवर्तनकारी प्रणाली की परिकल्पना करती है । यह नई दृष्टि पुराने अकादमिक ढाँचों को तोड़ने और विश्वविद्यालयों को ऐसे गतिशील वातावरण बनाने के लिए सशक्त बनाने की आकांक्षा रखती है जहाँ रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, व्यावहारिक कौशल और नैतिक मूल्य फल-फूल सकें । अपने मूल में, यह नीति न केवल अधिक रोज़गार-योग्य स्नातकों का, बल्कि विचारशील, अनुकूलनशील और सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार नागरिकों का भी पोषण करना चाहती है - एक ऐसा कदम जो भारत की शैक्षिक विरासत की ओर एक लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी है और 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया भी है । यह निबंध नीति के दर्शन, संरचना और वैश्विक प्रासंगिकता के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी सुधार की संभावनाओं और जटिलता का पता लगाता है ।

कठोर विशेषज्ञता की विरासत से लचीलेपन की नई वास्तुकला तक

दशकों से, भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली कठोर विशेषज्ञता के प्रतिमान में फँसी रही है, जहाँ छात्र, अक्सर किशोरावस्था में ही, संकीर्ण क्षेत्रों - कला, विज्ञान, वाणिज्य - को चुनते थे और शायद ही कभी इन अदृश्य सीमाओं को पार करते थे । शैक्षणिक नियति में बंधी प्रारंभिक ट्रैकिंग और संस्थागत अनम्यता का अर्थ था कि जीवन के अप्रत्याशित मोड़ आसानी से एक शैक्षणिक करियर को पटरी से उतार सकते थे। एनईपी-2020 इस परंपरा के बिल्कुल विपरीत है, और इसके बजाय यह अनिवार्य करता है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) एक लचीले, बहु-विषयक मॉडल की ओर बढ़ें[1]।

नीति के सबसे क्रांतिकारी कदमों में से एक है, एक मॉड्यूलर डिग्री संरचना की शुरुआत करना जिसमें कई प्रवेश और निकास बिंदु हों, साथ ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की अवधारणा भी शामिल हो । छात्र अब अपने पहले वर्ष के बाद एक प्रमाणपत्र, दो के बाद एक डिप्लोमा, तीन के बाद एक मानक स्नातक और चार साल के बाद शोध सहित स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। संचित क्रेडिट को संग्रहीत, स्थानांतरित और औपचारिक शिक्षा में भविष्य में पुनः प्रवेश के लिए उपयोग किया जा सकता है[2] । यह कदम पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। छात्रों के लिए, विशेष रूप से वंचित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय अब "सब कुछ या कुछ नहीं" वाला जुआ नहीं रह गया है।

इसके बजाय, सीखना एक आजीवन, बाधित और फिर से शुरू होने वाली यात्रा बन जाती है, जहाँ हर कदम को सम्मानजनक और मान्यता प्राप्त होती है।

J. Delors जैसे विद्वानों ने सुझाया है, ऐसे लचीले रास्ते केवल पहुँच के तंत्र ही नहीं हैं, बल्कि उन छात्रों की वास्तविक वास्तविकताओं को भी प्रमाणित करते हैं जिनकी प्रगति अरैखिक हो सकती है। इस प्रकार यह नीति आंशिक पूर्णता को सम्मान देती है और निरंतर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के द्वार खोलती है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ NEP-2020 की प्रतिबद्धता संरचनात्मक और दार्शनिक दोनों है - यह विश्वविद्यालय को निरंतर वापसी और नवीनीकरण के स्थान के रूप में पुनर्कल्पित करने का निमंत्रण है।

समग्र और बहुविषयक शिक्षा: जड़ों की ओर वापसी और भविष्य की ओर छलांग

संरचना में यह लचीलापन, NEP-2020 की बहु-विषयक, उदार शिक्षा की वकालत में अपनी सच्ची भावना प्रकट करता है। यह नीति भारत के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों, जैसे नालंदा और तक्षशिला, की भावना को प्रतिबिंबित करती है, जहाँ "कई कलाओं का ज्ञान" - विज्ञान, दर्शन, गणित, साहित्य, शिल्प और प्रदर्शन कला सहित - एक पूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक माना जाता था[3]। आज, जब दुनिया तेज़ी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन, वैश्वीकरण और पर्यावरणीय संकटों की चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे व्यापक-आधारित शिक्षण की एक बार फिर माँग बढ़ गई है।

जहाँ पिछली शताब्दी में अत्यधिक विशिष्ट विशेषज्ञता को महत्त्व दिया गया था, वहीं वर्तमान युग उन लोगों को तेज़ी से पुरस्कृत कर रहा है जो विभिन्न विषयों में विचारों का संश्लेषण कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं, और अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए रचनात्मक रूप से अनुकूलन कर सकते हैं। तदनुसार, NEP-2020 का लक्ष्य है कि 2040 तक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बहु-विषयक संस्थानों में बदल दिया जाए। उदाहरण के लिए, छात्र भौतिकी में मुख्य विषय के साथ-साथ संगीत और पर्यावरण अध्ययन में गौण विषय चुन सकते हैं; साहित्य का छात्र अर्थशास्त्र या कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रमों के साथ अपने पाठ्यक्रम को पूरक बना सकता है। इसका उद्देश्य बौद्धिक अंतर-परागण है, जहाँ नवाचार को विभिन्न विषयों के मिलन बिंदु पर बढ़ावा दिया जाता है और जहाँ समस्या-समाधान वास्तविक दुनिया में, एकीकृत तरीके से होता है।

इस व्यापकता का कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम चयन से कहीं आगे जाता है। एनईपी-2020 के तहत, शिक्षण पद्धति में भी बदलाव लाना होगा: सीखना रटने से आगे बढ़कर पूछताछ, चर्चा और व्यावहारिक परियोजनाओं की ओर बढ़ना चाहिए[4]। असाइनमेंट, समुदाय-आधारित पहल, इंटर्नशिप और शोध को अतिरिक्त के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा के उद्देश्य के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। इस अर्थ में, यह नीति डेवी (1938) के अनुभवात्मक शिक्षा के आह्वान के साथ-साथ आधुनिक नियोक्ताओं की माँगों को भी प्रतिध्वनित करती है, जो केवल विषयवस्तु विशेषज्ञों की तुलना में रचनात्मक और नैतिक विचारकों को अधिक महत्त्व देते हैं[5]।

शैक्षणिक-व्यावसायिक अंतर को पाटना: श्रम की गरिमा को बढ़ाना

एनईपी-2020 के तहत शायद सबसे सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण सुधारों में से एक, मुख्यधारा की उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की इसकी प्रतिबद्धता है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को गौण मानता रहा है, और अक्सर उन लोगों के लिए आरक्षित रखता है जो नियमित शिक्षा का "सामंजस्य" नहीं रख पाते। इसने मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों को और गहरा किया है और अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण कौशलों को हाशिए पर धकेल दिया है।

नीति इस द्वंद्व को निर्णायक रूप से दूर करती है[6]। सभी छात्रों को, चाहे उनकी शैक्षणिक प्रगति कुछ भी हो, व्यावसायिक शिल्प, इंटर्नशिप और कार्यस्थल-आधारित शिक्षा से परिचित कराया जाना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक कम से कम आधे छात्रों को महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना है। इस प्रकार, ईमानदार श्रम और व्यावहारिक कौशल की गरिमा—चाहे वह बढ़ईगीरी हो, कोडिंग हो या पाक कला -विश्वविद्यालय जीवन के केंद्र में पुनः स्थापित की गई है। यह कदम न केवल रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ाता है[7]; बल्कि यह इस बात का प्रतीकात्मक दावा भी है कि हाथों से सीखना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि दिमाग से सीखना।

इसके अलावा, इंटर्नशिप, सामुदायिक परियोजनाएँ और उद्योग-सहयोगी अनुसंधान जैसे अनुभवात्मक तत्वों को ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थानों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान सामाजिक अनुप्रयोग से मिलता है[8]। शैक्षणिक और व्यावसायिक के बीच सेतु का काम करते हुए, एनईपी-2020 छात्रों को अनुकूलनशील, नवोन्मेषी और लचीला बनने के लिए आमंत्रित करता है - ये गुण तेज़ी से बदलते तकनीकी परिदृश्यों का सामना कर रहे कार्यबल के लिए आवश्यक हैं[9]।

भारतीय ज्ञान का पुनः एकीकरण: संदर्भ और विश्वव्यापीकरण का मिलन

एनईपी-2020 जहाँ स्पष्ट रूप से वैश्विक मानकों पर ध्यान केंद्रित करती है—उदार कला महाविद्यालयों, शोध विश्वविद्यालयों और क्रेडिट-संचय ढाँचों से उधार लेते हुए—वहीं यह स्पष्ट रूप से भारतीय बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत की ओर लौटने की भी कोशिश करती है। नीति इस बात पर ज़ोर देती है कि "विश्वस्तरीय" शिक्षा स्थानीय स्तर पर आधारित होने के साथ-साथ वैश्विक रूप से प्रासंगिक भी होनी चाहिए।

इस उद्देश्य से, पाठ्यक्रम में भारत की शास्त्रीय और लोक परंपराओं, उसके दर्शन, स्वदेशी विज्ञान, पारंपरिक चिकित्सा, गणित और कलाओं को शामिल किया जाएगा[10]। यह प्रतिबद्धता केवल पुरानी यादों से कहीं आगे बढ़कर, इस मान्यता पर आधारित है कि महान सभ्यताएँ अपनी ज्ञान प्रणालियों से सांस्कृतिक आत्मविश्वास और नैतिक गहराई प्राप्त करती हैं—और साथ ही वैश्विक धाराओं के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए भी खुली रहती।

इस दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे स्नातक तैयार करना है जो विश्वव्यापी होने के साथ-साथ जड़ों से जुड़े भी हों; ऐसे नागरिक जो विज्ञान, वाणिज्य और कूटनीति के विश्व गलियारों में आसानी से आगे बढ़ सकें, तथा अपने समाज की जटिलताओं और शक्तियों से गहराई से जुड़े रहें।

ड्रॉपआउट कम करना और समावेशिता का निर्माण: समग्र शिक्षा का सामाजिक वादा

एक शिक्षा प्रणाली का मापदंड अंततः उन कुछ लोगों से नहीं होता जिन्हें वह आगे बढ़ाती है, बल्कि उन लोगों से होता है जिन्हें वह शामिल करती है। भारत की स्थायी चुनौतियाँ—उच्च ड्रॉपआउट दर, शहरी-ग्रामीण विभाजन और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए पहुँच में अंतर—दशकों से सुधारों का विरोध करती रही हैं। एनईपी-2020 का समाधान न केवल पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाना है, बल्कि संरचनात्मक लचीलापन और व्यापक समर्थन तंत्र तैयार करना भी है[11]।

प्रवेश-निकास बिंदुओं की बहुलता, पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा को मान्यता, और सामाजिक-भावनात्मक समर्थन पर ज़ोर, इन सभी का उद्देश्य शिक्षार्थियों को व्यवस्था में बनाए रखना है। क्षेत्रीय संस्थानों को स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए सशक्त बनाकर, यह नीति शहरी-ग्रामीण अंतर को भी पाटती है, जबकि राष्ट्रीय मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि गुणवत्ता कम न हो[12]।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एनईपी-2020 सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों पर विशेष ध्यान देने का आदेश देती है, जिसमें लक्षित छात्रवृत्तियाँ, लचीले प्रवेश और मज़बूत सहायता केंद्र शामिल हैं[13]। वास्तविक समावेशन के लिए ऐसे कदम ज़रूरी हैं, जैसा कि यूनेस्को के शिक्षा 2030 एजेंडा और भारतीय शिक्षा साहित्य में भी प्रतिध्वनित होता है[14]।

संकाय सशक्तिकरण और संस्थागत नवाचार

यदि संकाय नौकरशाही की जड़ता या स्वायत्तता के अभाव से विवश रहेंगे, तो केवल पाठ्यक्रम में सुधार करना ही पर्याप्त नहीं है। एनईपी-2020 इस पर सीधा ध्यान केंद्रित करता है, और संकाय को पाठ्यक्रम के सह-निर्माता, शोधकर्ता और सामुदायिक मार्गदर्शक के रूप में देखता है। व्यावसायिक विकास, शोध सहायता और नई करियर प्रगति प्रणालियाँ इस दृष्टिकोण का अभिन्न अंग हैं, साथ ही जीवंत, स्वायत्त, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों के पक्ष में पुराने संबद्धता और एकल-धारा मॉडल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजनाएँ भी हैं।

इस तरह के सुधार भारतीय उच्च शिक्षा को एएसीएंडयू जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अनुरूप लाते हैं, जो लंबे समय से रोजगार और लोकतांत्रिक नागरिकता दोनों के लिए "एकीकृत शिक्षा" को केंद्रीय मानते रहे हैं।

वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा: 21वीं सदी का सामना

एनईपी-2020 का दार्शनिक मूल संभवतः उदार शिक्षा के एक नए रूप का आह्वान है। इसका उद्देश्य न तो केवल आर्थिक उत्पादकता है और न ही तथ्यों का निष्क्रिय संचय, बल्कि एक अस्थिर दुनिया की अनिश्चितताओं और नैतिक दुविधाओं से जूझने के लिए तैयार स्वतंत्र, रचनात्मक और नैतिक मस्तिष्कों का विकास है।

वैश्विक अध्ययन, साथ ही भारतीय शोध Labaree, D. इस बात की पुष्टि करते हैं कि अंतःविषयक, व्यापक-आधारित शिक्षा उच्च नवाचार, चपलता और नेतृत्व के साथ सहसंबंधित है - ऐसे गुण जिन्हें भारत को राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने युवाओं में विकसित करना चाहिए।

आगे की राह: अवसर, चुनौतियाँ और कार्यान्वयन की परीक्षा

अपनी तमाम उम्मीदों के बावजूद, NEP-2020 का परिवर्तन न तो सरल है और न ही अपरिहार्य । इसके कार्यान्वयन के लिए संकाय प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, बुनियादी ढाँचे (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) और डिजिटल पहुँच में भारी निवेश की आवश्यकता है[15]। नियामक प्रणालियों में व्यापक बदलाव किया जाना चाहिए, उद्योग और नागरिक समाज के साथ साझेदारी को और मज़बूत किया जाना चाहिए, और शासन को जवाबदेह और सक्षम बनाया जाना चाहिए।

फिर भी बदलाव पहले से ही दिखाई दे रहा है: कई अग्रणी संस्थान - अशोक विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मानविकी को एकीकृत करने वाले आईआईटी, और अन्य - ने फाउंडेशनल वर्षों, क्रेडिट बैंकों और बहु-विषयक मार्गों के साथ प्रयोग शुरू कर दिए हैं। कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव ने मिश्रित और ऑनलाइन शिक्षा के प्रति खुलेपन को भी तेज़ कर दिया है ।

एनईपी-2020 की मूल भावना इस मान्यता पर आधारित है कि शिक्षा एक सार्वजनिक वस्तु और एक बुनियादी अधिकार है -लोकतंत्र और सामाजिक गतिशीलता की आधारशिला । इस नीति में 6% जीडीपी निवेश और मज़बूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी का आह्वान सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा ।

निष्कर्ष: लोकतंत्र और नवाचार की नर्सरी के रूप में विश्वविद्यालय

निष्कर्षतः, एनईपी-2020 का खाका केवल भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार नहीं करता; बल्कि इसे ज़मीनी स्तर से बदलने का प्रयास करता है । अनुशासनात्मक सीमाओं को तोड़कर, व्यावसायिक और स्थानीय ज्ञान को प्रतिष्ठित करके, और भारतीय तथा वैश्विक, दोनों परंपराओं में शिक्षा को जड़ से स्थापित करके, यह नीति विश्वविद्यालय को रचनात्मक, नैतिक और आजीवन विकास के एक स्थल के रूप में पुनर्परिभाषित करती है ।

बेशक, अंतिम परीक्षा क्रियान्वयन में होगी—क्या अलग-अलग संस्थान, संकाय और राज्य प्रणालियाँ इस "नए दृष्टिकोण" को मूर्त रूप दे पाएँगे । फिर भी, इस महत्वाकांक्षी मार्ग को निर्धारित करते हुए, NEP-2020 न केवल बेहतर नौकरियों या अधिक प्रतिस्पर्धी स्नातकों का वादा करता है; बल्कि यह एक ऐसे शैक्षिक अनुभव की संभावना भी प्रस्तुत करता है जो स्वतंत्र नागरिकों, विचारशील नेताओं और लचीले नवप्रवर्तकों का पोषण करता है । इस प्रकार, 21वीं सदी में भारतीय विश्वविद्यालय एक बार फिर लोकतंत्र और अन्वेषण, दोनों का केंद्र बन सकते हैं ।

संदर्भ –

- भारत सरकार। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय ।
- मिश्रा, आर. (2022). भारतीय शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. वाराणसी: ज्ञानदीप पब्लिकेशन.
- शर्मा, ए. (2023). उच्च शिक्षा में नवाचार: NEP-2020 की दृष्टि से. भोपाल: अकादमिक पब्लिशर्स.
- त्रिपाठी, एस. (2021). नई शिक्षा नीति 2020: प्रभाव और चुनौतियाँ. पटना: विद्या पब्लिशिंग हाउस.
- सिंह, के. (2021). एनईपी 2020 की समीक्षा और उच्च शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन
- जोशी, आर. (2022). एनईपी 2020 में बहु-विषयक दृष्टिकोण. भविष्य के लिए उच्च शिक्षा.
- शर्मा, एम. (2021). एनईपी 2020 और शिक्षक सशक्तिकरण. जर्नल ऑफ टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन
- NITI Aayog. (2018). Strategy for New India @75: Education. Government of India.
- UNESCO. (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action.

पादटिप्पणी –

[1] एनईपी-2020, अध्याय 11

[2] एनईपी-2020, अध्याय 11

[3] एनईपी -2020, अध्याय 11 और 22

[4] एनईपी-2020, अध्याय 11

[5] विश्व आर्थिक मंच, 2020

[6] एनईपी-2020, अध्याय 16

[7] नीति आयोग, 2018

[8] एनईपी-2020, अध्याय 11 और 16

[9] The German Dual Vocational Training System

[10] एनईपी-2020, अध्याय 11 और 22

[11] एनईपी-2020, अध्याय 3 और 10

[12] एनईपी-2020, अध्याय 11

[13] एनईपी-2020, अध्याय 6 और 14

[14] Multidisciplinary Education And Liberal Arts

[15] एनईपी-2020, अध्याय 23 और 24